



## भारत शासन अधिनियम, 1919

### परिचय

#### पृष्ठभूमि

वर्ष 1918 में राज्य सचिव एडविन सेमुअल मांटैग्यू (Edwin Samuel Montagu) और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने संवैधानिक सुधारों की अपनी योजना तैयार की, जिसे मांटैग्यू-चेम्सफोर्ड (या मॉट-फोर्ड) सुधार के रूप में जाना जाता है, जिसके कारण वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम को अधिनियमित किया गया।

वर्ष 1921 में मांटैग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों को लागू किया गया।

इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य भारतीयों का शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था।

अधिनियम ने केंद्र के साथ-साथ प्रांतीय स्तरों पर शासन में सुधारों की शुरुआत की।

### अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ

#### केंद्र स्तरीय सरकार:

##### ■ विषय:

- ऐसे मामले जो राष्ट्रीय महत्त्व के थे या एक से अधिक प्रांतों से संबंधित थे, केंद्र स्तरीय सरकार द्वारा शासित थे, जैसे: विदेश मामले, रक्षा, राजनीतिक संबंध, सार्वजनिक ऋण, नागरिक और आपराधिक कानून, संचार सेवाएँ आदि।
- इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधायिका को अधिक शक्तिशाली और जवाबदेह बनाया गया।

##### ■ कार्यपालिका:

- इस अधिनियम ने गवर्नर-जनरल को मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी बनाया।
- वायसराय की कार्यकारी परिषद में आठ सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया जिसमें तीन भारतीय सदस्यों को शामिल करना था।
- गवर्नर जनरल को अनुदानों में कटौती करने का अधिकार था, वह केंद्रीय विधायिका द्वारा लौटा दिये गए बलों को प्रमाणित कर सकता था तथा अध्यादेश जारी कर सकता था।

##### ■ विधानमंडल में सुधार:

- द्विसदनीय विधानमंडल: अधिनियम में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई जिसमें **निम्न सदन** या **केंद्रीय विधानसभा** ( Lower House or Central Legislative Assembly) और **उच्च सदन** या **राज्य परिषद** (Upper House or Council of State) शामिल थी।
- नए सुधारों के तहत अब केंद्रीय विधानमंडल के सदस्य को सरकार से प्रश्न पूछने, पूरक प्रश्न करने, स्थगन प्रस्ताव पारित करने तथा बजट के हिस्से पर मतदान करने का अधिकार था लेकिन अभी भी बजट के 75% हिस्से पर मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था।
- विधायिका का गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद पर वस्तुतः कोई नियंत्रण नहीं था।
- **निम्न सदन की संरचना:** निम्न सदन में 145 सदस्य थे, जो या तो मनोनीत थे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों से चुने गए थे। इसका कार्यकाल 3 वर्ष था।
  - 41 मनोनीत (26 आधिकारिक और 15 गैर-सरकारी सदस्य)
  - 104 निर्वाचित (52 जनरल, 30 मुस्लिम, 2 सिख, 20 वशिष्ठ)।
- **उच्च सदन की संरचना:** उच्च सदन में 60 सदस्य थे। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का था और इस सदन में केवल पुरुष सदस्य को ही शामिल किया गया था।
  - 26 मनोनीत
  - 34 निर्वाचित (20 जनरल, 10 मुस्लिम, 3 यूरोपीय और 1 सिख सदस्य)

##### ■ वायसराय की शक्तियाँ:

- वायसराय को विधायिका को संबोधित करने का अधिकार था।
- उसे बैठकों को आहूत करने, स्थगित करने या विधानमंडल को नरिस्त या खंडित करने का अधिकार प्राप्त रहा।

◦ वधायिका का कार्यकाल 3 वर्ष का था, जसै वायसराय अपने अनुसार बढा सकता था ।

#### ■ केंद्रीय वधानमंडल की शक्तियाँ:

◦ केंद्र सरकार को प्रांतीय सरकारों पर अप्रतिबंधित नयित्त्रण प्राप्त था ।

◦ केंद्रीय वधायिका को संपूर्ण भारत के लिये, सभी अधिकारियों और आम लोगों हेतु कानून बनाने के लिये अधिकृत किया गया था, चाहे वे भारत में हों या नहीं ।

#### ■ केंद्रीय वधायिका पर प्रतिबंध:

◦ वधायिका पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे:

◦ कसि वधियक को पेश करने हेतु गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था, जैसे- मौजूदा कानून में संशोधन या गवर्नर जनरल के अध्यादेश में संशोधन, वदिशी संबंध और भारतीय राज्यों, सशस्त्र बलों के साथ संबंध के मामले ।

◦ भारतीय वधायिका भारत के संबंध में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कसि भी कानून को बदल या उलट नहीं सकती थी ।

#### प्रांत स्तरीय सरकार:

##### ■ वषिय:

◦ इसमें वे मामले शामिल थे जो एक वशिष्ट प्रांत से संबंधित थे जैसे:

◦ सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, शक्ति, सामान्य प्रशासन, चिकित्सा सुविधाएँ, भूमि-राजस्व, जल आपूर्ति, अकाल राहत, कानून और व्यवस्था, कृषि आदि ।

##### ■ द्वैध शासन की शुरुआत:

◦ इस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर कार्यपालिका हेतु द्वैध शासन प्रणाली (दो व्यक्तियों/पार्टियों का शासन) की शुरुआत की ।

◦ द्वैध शासन (Diarchy) को आठ प्रांतों में लागू किया गया था जसमें

असम, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे, मद्रास और पंजाब प्रांत शामिल थे ।

◦ द्वैध शासन व्यवस्था के तहत प्रांतीय सरकारों को अधिक अधिकार प्रदान किये गए थे ।

◦ गवर्नर प्रांत का कार्यकारी प्रमुख था ।

##### ■ वषियों का वभाजन:

◦ वषियों को दो सूचियों में वभाजित किया गया था: 'आरक्षित' और 'स्थानांतरित' । आरक्षित सूची में शामिल वषियों का प्रशासन गवर्नर द्वारा नौकरशाहों की कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था ।

◦ इसमें कानून और व्यवस्था, वित्त, भू-राजस्व, सचिवाई आदि जैसे वषिय शामिल थे ।

◦ सभी महत्त्वपूर्ण वषिय को प्रांतीय कार्यकारिणी के आरक्षित वषियों में शामिल किया गया ।

◦ हस्तांतरित वषियों को वधान परिषद के नरिवाचित सदस्यों में से मनोनीत मंत्रियों द्वारा प्रशासित किया जाना था ।

◦ इसमें शक्ति, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार, उद्योग, कृषि, उत्पाद शुल्क आदि वषिय शामिल थे ।

◦ प्रांत में संवैधानिक तंत्र के वफल होने की स्थिति में गवर्नर हस्तांतरित वषियों का प्रशासन भी अपने हाथ में ले सकता था ।

##### ■ हस्तक्षेप पर प्रतिबंध :

◦ भारत के राज्य सचिव और गवर्नर जनरल आरक्षित वषियों (Reserved Subjects) के संबंध में हस्तक्षेप कर सकते थे, जबकि स्थानांतरित वषियों (Transferred Subjects) के संबंध में उन्हें हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त नहीं था ।

##### ■ वधानमंडल में सुधार:

◦ प्रांतीय वधान परिषदों का और अधिक वसितार किया गया तथा 70% सदस्यों का चुनाव किया जाना था ।

◦ सांप्रदायिक (Communal) और वर्गीय मतदाताओं (class electorates) की व्यवस्था को और मज़बूत किया गया ।

◦ महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया ।

◦ वधान परिषदें बजट को अस्वीकार कर सकती थीं लेकिन यदि आवश्यक हो तो गवर्नर इसे पुनः बहाल कर सकता था ।

◦ वधायकों (Legislators) को बोलने की स्वतंत्रता थी ।

##### ■ गवर्नर की शक्तियाँ:

◦ गवर्नर जिन्हें वह आवश्यक समझे, मंत्रियों को कसि भी आधार पर बर्खास्त कर सकता था । साथ ही उसने वित्त पर पूर्ण नयित्त्रण बनाए रखा ।

◦ वधान परिषदें कानून नरिमाण की प्रक्रिया शुरू कर सकती थीं लेकिन उसके लिये गवर्नर की सहमति की आवश्यकता थी ।

◦ गवर्नर को वधियक पर वीटो शक्ति का अधिकार था तथा वह अध्यादेश जारी कर सकता था ।

#### अधिनियम का महत्त्व:

■ भारतीयों में जागृति: इस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को प्रशासन के बारे में गुप्त सूचना मिली और वे अपने कर्तव्यों के प्रति जागृक हुए ।

◦ इससे भारतीयों में राष्ट्रवाद और जागृतिकी भावना पैदा हुई और वे स्वराज के लक्ष्य (Goal of Swaraj) को प्राप्त करने की दशा में आगे बढ़े ।

■ मतदान के अधिकारों का वसितार: भारत में चुनाव क्षेत्रों का वसितार हुआ जससे लोगों में मतदान के महत्त्व के प्रति समझ बढ़ी ।

■ प्रांतों में स्वशासन: इस अधिनियम ने भारत में प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत की ।

◦ इस अधिनियम ने लोगों को प्रशासन करने का अधिकार प्रदान किया जससे सरकार पर प्रशासनिक दबाव बहुत कम हो गया ।

◦ इसने भारतीयों को प्रांतीय प्रशासन में ज़िम्मेदारियों का नरि्वहन करने हेतु तैयार किया ।

#### अधिनियम की कमियाँ:

- **गैर-ज़मिंदार केंद्र सरकार:** अधिनियम में अखलि भारतीय सत्तर पर कसी भी ज़मिंदार सरकार की परकिल्पना नहीं की गई।
- **सांप्रदायिकता का प्रसार:** तरुटपूरण चुनावी प्रणाली और सीमति मताधिकार लोकप्रयिता हासलि करने में वफिल रहे। एक अलग चुनावी प्रणाली ने सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दिया।
- **मतदाताओं का सीमति वसितार:** केंद्रीय वधायिका में मतदाताओं की संख्या लगभग 1.5 मलियन तक बढ़ा दी गई थी, जबकएक अनुमान के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 260 मलियन थी।
- **प्रशासनिक नयितरण का अभाव:** केंद्र में वायसराय और उसकी कार्यकारी परषिद पर वधायिका का कोई नयितरण नहीं था।
  - प्रांतीय मंत्रयिों का वतित और नौकरशाहों पर कोई नयितरण नहीं था; इससे दोनों के मध्य लगातार संघर्ष की सथतिबनी हुई थी।
  - मंत्रयिों से अक्सर महत्त्वपूरण मामलों पर भी परामर्श नहीं कयिता जाता था और गवरनर द्वारा कसी भी मामले पर जसिे बाद में वशेष माना जाता था, उसे खारजि कर दिया जाता था।
  - गवरनर को अप्रतबिंधति शक्तयिों प्राप्त थी, वह अपनी परषिद और मंत्रयिों के नरिणय के वरिद्ध भी नरिणय ले सकता था।
    - प्रशासन से संबंधति लगभग सभी महत्त्वपूरण मामले राज्यपाल पर नरिभर थे।
- **वषियों का अनुपयुक्त वभिजन:** केंद्र में वषियों का वभिजन उचति एवं संतोषजनक नहीं था।
  - केंद्रीय वधायिका को बहुत कम शक्ति दी गई थी और वतित पर उसका कोई नयितरण नहीं था।
  - प्रांतों के सत्तर पर, वषियों का वभिजन और समानांतर प्रशासन दोनों ही तरकहीन एवं अव्यावहारिक थे। सचिाई, वतित, पुलसि, प्रेस और न्याय जैसे वषिय 'आरक्षति' श्रेणी में शामिल थे।

### अधिनियम के परणाम:

- **सार्वजनिक प्रतिकरिया:** कॉनग्रेस ने अगस्त 1918 में हसन इमाम की अध्यक्षता में बॉम्बे में एक वशेष सत्तर में बैठक की और सुधारों को "नरिशाजनक" एवं "असंतोषजनक" घोषति कयिता तथा इसके सथान पर प्रभावी स्वशासन की माँग की।
  - **बाल गंगाधर तलिक** (Bal Gangadhar Tilak) द्वारा मॉटफोर्ड सुधारों को "अयोग्य और नरिशाजनक - एक धूप रहति सुबह" कहा गया था।
  - एनी बेसेंट ने सुधारों को "इंग्लैंड के प्रस्ताव के योग्य और भारत को स्वीकार करने के लयि अयोग्य" पाया।
  - सुरेंद्रनाथ बनरजी (Surendranath Banerjee) के नेतृत्व में वयोवृद्ध कॉनग्रेसी नेता सरकारी प्रस्तावों को स्वीकार करने के पक्ष में थे।
- **शक्ति हेतु संघर्ष:** अधिनियम ने भारतीयों और अंगरेजों दोनों में सत्ता के लयि संघर्ष को प्रोत्साहति कयिता।
  - परणामस्वरूप बड़ी संख्या में सांप्रदायिक दंगे हुए जो वर्ष 1922 से 1927 तक जारी रहे।
  - वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी (Swaraj Party) की स्थापना हुई तथा उसने चुनावों में मद्रास को छोड़कर पर्याप्त संख्या में सीटें जीती।
    - जबकि पार्टी बंबई और मध्य प्रांतों में मंत्रयिों के वेतन के साथ अन्य वस्तुओं की आपूर्ति को अवुरुद्ध करने में सफल रही।
    - इस प्रकार दोनों प्रांतों के गवरनरों को द्वैध शासन को समाप्त करने हेतु मजबूर होना पड़ा और स्थानांतरति वषियों को अपने नयितरण में ले लयिता गया।
- **रॉलेट एक्ट अधिनियमन:** भारतीयों को शांत करने के लयि भारत सरकार दमन के लयि तैयार थी।
  - पूरे युद्ध के दौरान राष्ट्रवादयिों का दमन जारी रहा। क्रांतिकारयिों का दमन कयिता गया, उन्हें फाँसी दी गई और जेल में डाल दिया गया।
  - मौलाना अबुल कलाम आज़ाद (Maulana Abul Kalam Azad) जैसे कई अन्य राष्ट्रवादयिों को भी जेल में डाल दिया।
  - सरकार ने अब खुद को और अधिक दूरगामी शक्तयिों से लैस करने का फ़ैसला कयिता, जो कानून के शासन के स्वीकृत सदिधांतों के खलिाफ थी, ताकि उन राष्ट्रवादयिों की आवाज को दबाया जा सके जो सरकारी सुधारों से संतुष्ट नहीं थे।
  - मार्च 1919 में **रॉलेट एक्ट** (Rowlatt Act) पारति कयिता, हालाँकि केंद्रीय वधिान परषिद के प्रत्येक भारतीय सदस्य ने इसका वरिोध कयिता।
    - इस अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतविधिंयिों को दबाने के लयि अधिकार प्रदान कयि और दो साल तक बनिा कसी मुकदमे के राजनीतिक कैदयिों को हरिसत में रखने की अनुमति दी।
    - इस अधिनियम ने सरकार को **बंदी प्रत्यक्षीकरण** (Habeas Corpus) के अधिकार को नलिंबति करने का अधिकार प्रदान कयिता जसिने बरटिन में नागरिक स्वतंत्रता की नीव रखी।